"आपका अपना टेलीफोन" (ओ.वाई.टी.) स्वीकृत करने के लिए बनाया गया कार्यक्रम

638. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग ने "आपका अपना टेलीफोन" (ओ०वाई०टी०) श्रेणी के अन्तर्गत जून, 1991 तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर दिसम्बर, 1991 तक तथा गैर-ओ०वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत दिसम्बर, 1984 तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर दिसम्बर, 1992 तक टेलीफोन स्वीकृत करने का एक कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी के आवेदकों की सीमा दिसम्बर 1984 तक निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सीमा को आगे बढ़ाने का विचार रखती है क्योंकि निर्धारित की गई सीमा और टेलीफोन स्वीकृति की समय सीमा के बीच बहुत अधिक अन्तर है ?

श्री पी०वी० रंगैया नायडू संचार मंत्रालय में उप मंत्री (क) जी हां । बम्बई और दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदकों की प्रतीक्षा सूची निपटाने के सम्बन्ध में नीचे दिए अनुसार एक कार्यक्रम तैयार किया गया है :—

श्रेणी	पंजीकरण की अवधि	निपटाए जाने की तिथि
ओ०वाई०टी०	जून, 1991	दिसम्बर, 1991
विशेष	जून, 1991	दिसम्बर, 1991
गैर-ओ०वाई टी० सामान्य	दिसम्बर, 1984	मार्च, 1992

(ख) और (ग) इस समय उपलब्ध सीमित स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए, गैर-ओ०वाई०टी श्रेणी में दर्ज आवेदकों की संख्या उपलब्ध करवाई जा रही अतिरिक्त क्षमता की तुलना में कहीं अधिक है । तथापि, गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी में और अधिक टेलीफोन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

दिल्ली परिवहन निगम का निजीकरण

639. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "प्राइवेटाईजेशन इज आनली ब्योर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही बसों की प्रति किलोमीटर प्रचालन लागत पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गयी है, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के किराये कितनी बार बढ़े हैं और कितने-कितने बढ़े हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालन लागत (प्रति कि.मी.) बढ़ गई है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(प्रति कि०मी० पैसे)

वर्ष	कार्य चालन खर्च (मूल्य ह्रास और ब्याज छोड़कर)
1988–89	539
1989–90	560
1990–91 (अनंतिम)	792

(ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के किराए फरवरी, 1986 में केवल एक बार संशोधित किए गए हैं जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

संशोधन से पहले		संशोधन के बाद	
दूरी कि.मी.	किराया पसों में	दूरी कि.मी. में	किराया पसों में
0—4	30	0—6	50
4—16	40	6—16	100
16—20	50	16+	150
20+	75		

Tackling of Kashmir situation

640. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL:

MAULANA OBAIDULAH KHAN AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS *be pleased to state:*

(a) whether the Coordination Committee on Kashmir (CCK), a human rights organisation, has accused the security forces of human indulging in large scale burning of residential and commercial localities and killing of innocent persons in Kashmir, has expressed pain at the reluctance of Government to prosecute guilty security personnel and its inability to provide adequate relief to Kashmir migrants;

(b) whether Government's attention has beeen drawn to the newsitem captioned "State terrorism in Valley: Forum" which appeared in the Times of India dated the 12th July, 1991; and

(c) if so, what is the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Government has seen the report brought out by "Co-ordination Committee on Kashmir" formed by some individuals, in which certain allegations of human rights violations by the security forces in Kashmir Valley and Government's inability to provide adequate relief to Kashmiri migrants have been made.

(b) Yes, Sir.

(c) Whether the terrorists are under pressure, they resort to deliberate disinformation campaign making wild allegations against the security forces to demoralise them; it is a part of their strategy to maintain psycological pressure on the security forces. Some of the people get affected by such disinformation campaign. However, wherever the complaints against the security forces are *prima-facie* established, these are investigated and disciplinary and other action is initiated erring personnel. Already criminal cases and Courts of Inquiry have been instituted.